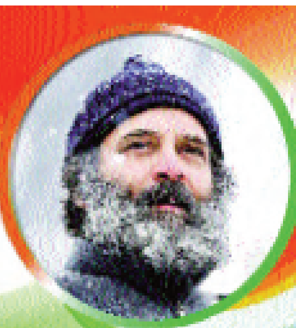

डिजीटल पत्र

कांग्रेस दर्पण

बिहार

दैनिक

पटना, 21 मार्च, मंगलवार, 2023

संपादक की कलम से

हमारे कांग्रेस कार्यकर्तागण हम अपने तमाम जिला अध्यक्षों, प्रखंड अध्यक्षों और तमाम कार्यकर्ता से निवेदन करते है कि कांग्रेस दर्पण में अपने जिले और प्रखंड अस्तर की खबर को भेजें जिसे हम प्रमुखता से स्थान देते हैं, यहां कोई भी छोटा और बड़ा नहीं समझा जाता। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी को एक ताकतवर अध्यक्ष प्राप्त हुआ है और ऐसे में हम कार्यकर्ताओं की जवाबदेही है कि कांग्रेस से जुड़ी हर बात की जानकारी माननीय अध्यक्ष और तमाम कार्यकर्ताओं तक पहुंचाएं।

कांग्रेस दर्पण जिसमें एक सशक्त माध्यम है। आज के इस डिजिटल दुनिया में कांग्रेस दर्पण का निर्माण कार्यकर्ताओं को मजबूती प्रदान करने की एक पहल है अकबर इलाहाबादी ने कहा था-

'ना बम निकालो ना तलवार निकालो जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो'

-डॉ0 संजय कुमार,
संपादक, कांग्रेस दर्पण सह कॉंग्रेस कार्यकर्ता। संपर्क -8252667278

मैं BJP-RSS से नहीं डरता।

चाहे मेरे खिलाफ कितने भी मामले दर्ज कर लें,
कितनी भी बार मेरे घर पुलिस भेज दें।
मैं फिर भी सच्चाई के लिए लड़ता रहूंगा।

-राहुल गांधी

कांग्रेस सेवादल संगठन

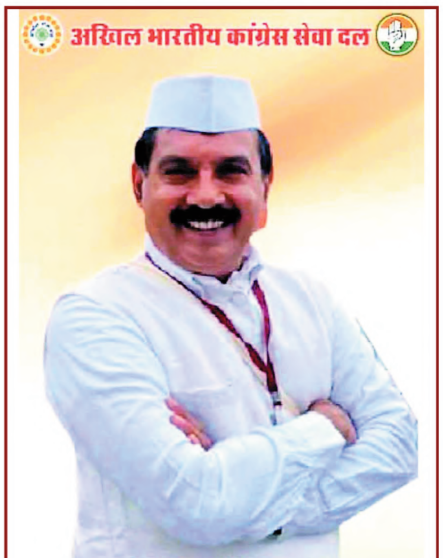

श्री लालजी देसाई
राष्ट्रीय अध्यक्ष, कांग्रेस सेवादल,

वक्त अच्छे–अच्छे को झुकाता हैं। वक्त सबका आता हैं।

अफरोज खान, राज्य प्रभारी
बिहार कांग्रेस सेवा दल

पटना। कांग्रेस दर्पण

कांग्रेस सेवादल राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से भी दो साल पुराना संगठन है. लेकिन एक ओर जहां बदलते दौर के साथ राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ मजबूत होता चला गया, वहीं कांग्रेस सेवादल नेपथ्य में चला गया. अब कांग्रेस सेवादल एक बार फिर से मुख्यधारा में लौटेगा और आरएसएस का मुकाबला करेगा. कांग्रेस पार्टी अपने इस हरावल दस्ते को भविष्य की जंग के लिए तैयार करने में जुटी है. कांग्रेस सेवादल का एक समृद्ध इतिहास रहा है, लेकिन बदलते वक्त के साथ सेवादल के पास सिर्फ पार्टी के कार्यक्र्मों में अनुशासन बनाए रखने की जिम्मेदारी रह गई. अब पार्टी इस संगठन का गौरव फिर से लौटाने की कवायद में जुटी है.

कांग्रेस सेवादल को अनुशासन और जज्बे के लिए जाना जाता हैं. सेवादल के संस्थापक डॉ. नारायण सुब्बाराव हार्डिकर और आरएसएस के संस्थापक केशव बलिराम हेडगेवार सहपाठी थे. हार्डिकर ने 28 दिसंबर 1923 को हिंदुस्तानी सेवादल के नाम से सेवादल का गठन किया था. जबकि हेडगेवार ने 27 सितंबर 1925 में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना की थी. आजादी की लड़ाई में सेवादल ने प्रमुख भूमिका निभाई थी. 7 मार्च 1947 में इसका नाम हिन्दुस्तानी सेवादल से बदलकर कांग्रेस सेवादल कर दिया गया. पंडित जवाहर लाल नेहरू इसके पहले अध्यक्ष थे. इसे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल के सपनों का संगठन कहा जाता हैं।

कांग्रेस सेवादल उद्देश्य

कांग्रेस सेवादल का मुख्य उद्देश्य संगठन को मजबूत करना। जिससे सेवादल जर्मीनी स्तर से प्रदेश लेवल तक प्रदेश के सरकार को मजबूती प्रदान कर सकें। क्योंकि सेवादल संस्थापक डॉक्टर एन.एस. हार्डिकर जी का कहना था। जबतक सेवादल मजबूत नहीं होगा, तब तक एक सुन्दर सुनहरा भविष्य की कल्पना नहीं कर सकते हैं। इसलिए सेवादल को सभी प्रकार से सशक्त बनाना हैं। ग्रामीण अंचलों में कार्यकर्ताओं के साथ ताल से ताल मिलाकर चलना होगा।

जनहित में कार्य कर गाँव के ग्रामीणों के छोटे से छोटे समस्या को लेकर उनके समस्याओं का निराकरण करना, एवं शासन के तमाम योजनाओं की जानकारी से अवगत कराना। जिससे लोग हमसे और हमारे कांग्रेस पार्टी से अधिक से अधिक जुड़े। ग्रामीणों के हित में काम कर अपने और अपने कांग्रेस पार्टी के प्रति विश्वास बढ़ाना। लोगों के दिलों में पूरी सिद्दत से कांग्रेस पार्टी के लिए जगह बनाना लोगों के दिलों में उत्सुकता जगाना। हमारी पार्टी आगे बढ़ेंगे और सबका का साथ, सहयोग और आशिर्वाद मिलेगा। हर हिंदुस्तानी को सेवादल से जुड़ना चाहिए, देश व समाज के उत्थान लिए आमजनों के लिए अति आवश्यक हैं। अपना कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ेंगी । क्योंकि सेवादल किसी जाति, धर्म, संप्रदाय में भेदभाव नहीं करता हैं।

-राम कुमार आजाद,
सेवादल, जमालपुर, मुंगेर, बिहार

जय हिंद साथियों

आशा है आप तमाम लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे

बहुत ही जल्द बिहार प्रदेश कांग्रेस सेवादल मुख्यालय सदाकत आश्रम पटना में कांग्रेस सेवादल का तीन दिवसीय प्रशिक्षण सहयोगी शिविर लगने जा रहा है जो भी साथी इच्छुक हैं कृपया कार्यालय प्रभारी श्री बिपिन झा (9931986181) से संपर्क कर उन्हें अपना नाम पता मोबाइल नंबर दर्ज करवाएं . प्रशिक्षण की तिथि जल्दी घोषणा होगी

धन्यवाद
अफरोज खान, राज्य प्रभारी
बिहार कांग्रेस सेवा दल

बिहट: फ्लाईओवर की मिली स्वीकृति

पटना।कांग्रेस दर्पण

बेगूसराय जिले के बिहट नगर परिषद में बनने वाले फ्लाईओवर के लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी को बिहार प्रदेश कांग्रेस के जनप्रिया सम्मानित अध्यक्ष पूर्व केंद्रीय मंत्री राज्यसभा सांसद डॉ अखिलेश प्रसाद सिंह के द्वारा बिहट नगर परिषद वासियों की ओर से लिखे गए पत्र के आलोक में आज फ्लाईओवर की स्वीकृति मिली. इसके लिए हम अपने सम्मानित नेता डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह को बेगूसराय वासियों की ओर से एवं नगर कांग्रेस कमिटी नगर निगम बेगूसराय की ओर से इस जनहित कार्य के लिए आभार व्यक्त करते हैं बहुत बहुत-बहुत बधाई.

ब्रजेश कुमार प्रिंस पूर्व पार्षद अध्यक्ष नगर कांग्रेस कमिटी नगर निगम बेगूसराय

वर्ष 2004 से 2009 एवं 2009 से 2014 कांग्रेस की यूपीए 1 एवं 2, सरकार ने अनुभवी प्रधानमंत्री ,डॉक्टर मनमोहन सिंह एवं चेयरपर्सन आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी तथा युवा नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में सम्पूर्ण भारत के जनहित में , 16 केंद्र प्रायोजित योजना

1. महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना 2. सर्व शिक्षा अभियान 3. मध्यान भोजन 4. जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण योजना 5. इंदिरा आवास योजना 6. राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम 7. प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना 8. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 9 समन्वित बाल विकास सेवा परियोजना 10 त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम 11. संपूर्ण स्वच्छता अभियान 11. त्वरित सिंचाई कार्यक्रम12. राष्ट्रीय बागवानी मिशन13. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 14. राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना 15. हरित ऊर्जा विकास एवं सुधार कार्यक्रम 16. राजीव आवास योजना के इलावे पिछड़े राज्यों को अरबों रुपए के साथ ही विशेष पैकेज के रूप में मुंह मांगा राशि बुनियादी सुविधा , जैसे बिजली, शिक्षा कृषि, स्वास्थ्य, सिंचाई एवं उद्योग धंधे को विकसित करने के लिए दी गई। किसानो के कर्ज माफी के साथ साथ अलग से केंद्र और राज्य के संयुक्त 54 योजनाओं , को कांग्रेस पार्टी ने अपने अनुभवी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में धरातल पर उतारा। बीजेपी के मोदी सरकार ने भारत में, अपने मित्रों के सहयोग से, पकौड़े, का कारखाना आवश्य खुलवा दिया है ।

-हारून रशीद खान, पूर्व सांसद प्रतिनिधि बेगूसराय,पूर्व चेयरमैन ,फ्लैगशिप मॉनिटरिंग कमिटी, सह पूर्व सदस्य ,बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी ।

नई दिल्ली एआईसीसी ऑफिस अखिल भारतीय कांग्रेस बिहार के प्रभारी माननीय श्री भक्त चरण दास जी के साथ एवं बिहार के युवा कांग्रेस के साथी कुमार आशीष जी ऑल इंडिया कांग्रेस ऑफिस के परागण का या

बेगूसराय जिला के मटिहानी प्रखंड के महेंद्रपुर निवासी 103बर्षीय झन झन कांग्रेसी श्री रामेश्वर झा जी अब हमारे बीच नहीं रहे जिला कांग्रेस कमिटी एवं प्रखंड कांग्रेस कमिटी दुवारा तिरंगा झंडा एवं फूल माला से उनके पार्थिव शरीर पर तिरंगा झंडा एवं फूल माला दिया गया इस अबसर पर जिला कांग्रेस के नेता रामबिलास सिंह पूर्व बी पी सी सी सदस्य मो मतीन अख्तर कांग्रेस नेता रामचंद्र सिंह सुबोध कुमार राजदेव सिंह प्रखंड अध्यक्ष रामानुज कुंवर अनिल कुमार नवीन सिंह गणेश झा माको दा रामकिशोर सिंह राजनीती सिंह रामलगन सिँह दिनेश सिँह आदि सैकड़ो लोगो ने फूल माला दिये

पटना स्थित सी डी ए कार्यालय को कोलकाता स्थानांतरित करने की केंद्र सरकार की कवायद के खिलाफ बिहारवासियों मे आक्रोश

पटना ।कांग्रेस दर्पण

बिहार प्रदेश कांग्रेस कमिटी के प्रदेश प्रतिनिधि सह क्षेत्रीय प्रवक्ता सह सी डी ए बचाओ संघर्ष समिति के संयोजक प्रो विजय कुमार मिठू , सह संयोजक पूर्व विधायक मो खान अली, महासचिव पुरुषोत्तम मिश्रा, सचिव अमरजीत कुमार, सी डी ए सेवानिवृत स्टाफ एसोसिएशन के अध्यक्ष अनुपम कुमार, उदय शंकर पालित, दामोदर गोस्वामी , शिव कुमार चौरसिया, आदि ने कहा की बिहार के एकमात्र रक्षा लेखा नियंत्रक कार्यालय जिसकी स्थापना पूर्व राष्ट्रपति देशरत्न डा राजेंद्र प्रसाद के प्रयास से 77 वर्ष पहले किया गया था , जिसे रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अपग्रेड कर कोलकाता स्थानांतरित करने की कवायद काफी तेज होने से यहां से कर्मचारी , बिहार के सभी सैन्य संस्थान में कार्यरत स्टाफ, तथा बिहार के आम आवाम में भारी आक्रोश है, जिसके खिलाफ कल दिनांक 22 मार्च को 11:30 बजे दिन से पटना स्थित सी डी ए कार्यालय के समक्ष शांतिपूर्ण प्रदर्शन आयोजित कर महामहिम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षामंत्री एवम् मुख्यमंत्री बिहार के नाम ज्ञापन, डाक, ईमेल ,ट्वीट के माध्यम से भेजा जाएगा।

नेताओ ने कहा की पूर्व में भी कई बार पटना सी डी ए कार्यालय को कोलकाता स्थानांतरित करने का प्रयास किया गया था, जिसके खिलाफ पटना से दिल्ली तक संघर्ष समिति के बैनर तले सभी राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों, के शांतिपूर्ण आंदोलन एवम् मांग पर रक्षामंत्री ने स्थानांतरण रोकने का काम किए थे, परंतु अब फिर इसकी स्थानांतरण की प्रकिया तेज कर दी गई है ।

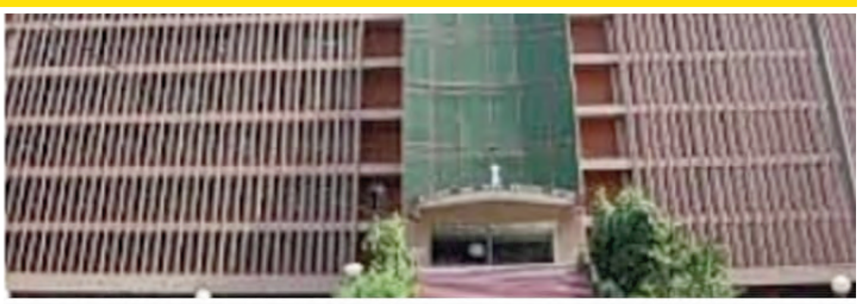

नेताओ ने कहा बिहार जैसे बड़े राज्य जहां केंद्रीय प्रतिष्ठान जनसंख्या, क्षेत्रफल, आवश्यकता के अनुरूप काफी कम है, तो दूसरी ओर यहां और संस्थाएं लाने की जगह वर्षो से स्थापित संस्था को दूसरे राज्य में स्थानांतरित किया जा रहा है।

नेताओ ने सभी राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों, आमजन से 22 मार्च के पटना सी डी ए कार्यालय के समक्ष आयोजित होने वाले महाधारणा में 11:30 बजे ज्यादा से ज्यादा संख्या में शामिल होने की कृपा करे।

बहन डॉ अंजलिजी यादव को राजस्थान प्रदेश महिला कांग्रेस सेवा दल प्रदेश अध्यक्ष मनोनीत होने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं

राजस्थान प्रदेश कांग्रेस सेवा दल आपके उज्जवल भविष्य की कामनाए करता है।

अरुण कुमार सोलंकी सुरसागर जोधपुर
वार्ड न, 4 उत्तर

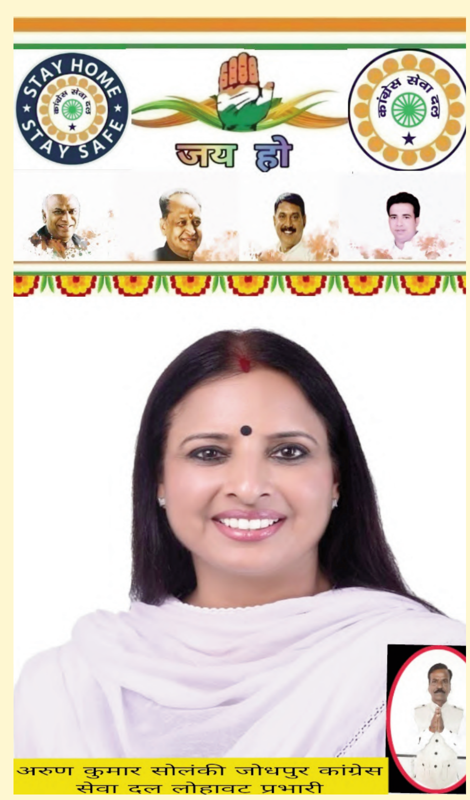

उत्तराखंड: राज्य सरकार का वर्ष(2023-2024) का बजट राज्य को दिशाहीन करने वाला है - राकेश राणा

पटना।कांग्रेस दर्पण

राज्य सरकार का वर्ष(2023-2024) का बजट राज्य को दिशाहीन करने वाला है राकेश राणा (2023 24) का बजट और राज्य का कर्ज बराबरी पर पहुंचा भाजपा की उपलब्धि

वर्ष 2023- 24 का बजट 15 मार्च 2000 23 को विधानसभा भराड़ीसैंण में वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल द्वारा प्रस्तुत किया गया।

कुल बजट जो प्रस्तुत किया गया वह 76 हजार 592 करोड़ 54 लाख का रहा।

पिछले साल की अपेक्षा इस बजट में 18.5% की वृद्धि देखी गई।

प्रदेश के अंदर 8 लाख 68 हजार बेरोजगार पंजीकृत हैं।

वर्ष 2022- 23 में राज्य सरकार के द्वारा 121 रोजगार मेले आयोजित किए गए जिसमें कुल 2299 लोगों को रोजगार मिला।

यह बजट यह बताता है कि राज्य पर कर्ज का कितना अधिक बोझ है फिलहाल राज्य को 6161 करोड़ का ब्याज देना पड़ रहा है।

एक पर्यटन प्रधान प्रदेश में पर्यटन का बजट 302 करोड़ का नाकाफी है।उत्तराखंड पर्यटन विकास निगम को मात्र 63 करोड़ का बजट देना बताता है कि वर्तमान सरकार प्रदेश में पर्यटन को विकसित करने की कितनी इच्छुक है।

पलायन आयोग की रिपोर्ट कहती है के उत्तराखंड में 6000 गांव ऐसे हैं जो कि सड़क विहीन हैं यानी 6000 से अधिक गांव में तक सड़क नहीं है वहीं दूसरी ओर पलायन आयोग की रिपोर्ट में यह भी दर्ज है कि 230 लोग हर 24 घंटे में पर्वतीय अंचलों से मैदानी इलाकों में पलायन कर रहे हैं ऐसे में जो तमाम योजनाएं सरकार के द्वारा घोषित की गई हैं कहीं ऐसा ना हो कि जब तक वह जमीन पर उतरें तब तक पूरा उत्तराखंड ही खाली हो जाय।

यह बात सर्वविदित है कि राज्य की कुल आमदनी 35000 करोड़ से ज्यादा की नहीं है वही बजट 77000 करोड़ के लगभग का है ऐसे में यह बजटीय घाटा कैसे पाटा जाएगा यह अपने आप में यक्ष प्रश्न है।

दरअसल कड़वी सच्चाई यह है कि देश में जीएसटी लागू होने के बाद से उत्तराखंड जैसे छोटे राज्यों को बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ रहा है। वसूली टारगेट के अनुसार नहीं हो पा रही है और इसीलिए राजकीय कोष यानी खजाना खाली है।

एक तरह से आगामी चुनाव के मद्देनजर यह बजट लोकलुभावन जरूर है। उद्यान विभाग में स्वरोजगार की संभावनाएं जताई गई हैं। हॉर्टिकल्चर फ्लोरीकल्चर इत्यादि में 813 करोड का बजट तो रखा गया है परंतु यदि प्रदेश के युवाओं को ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी तो कैसे स्वरोजगार के रास्ते खुलेंगे पता नही। नई-नई खेती और नई नई टेक्निक के लिए युवाओं की ट्रेनिंग बहुत जरूरी है वरना परंपरागत खेती से कितनी इनकम होगी और यह कितना प्रैक्टिकल है राज्य सरकार बताएं। वही उत्तराखंड का सेब देश विदेश में जिसकी बहुत डिमांड है उस एप्पल मिशन को नाम मात्र का बजट देना और पॉलीहाउस को 200 करोड़ का बजट देना सरकार की अदूरदर्शिता का ही परिणाम है।

उद्योग विभाग को 461करोड़ का जो बजट मिला है उसके सापेक्ष यह चिंतन करने की जरूरत है कि उद्योग लगने के बाद प्रदेश के युवा कितना लाभान्वित हुए? उनको रोजगार कितना मिला?

जो उद्योग यहां इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको प्रदेश सरकार की ओर से क्या सुविधाएं दी जा रही हैं और बदले में वह प्रदेश के युवाओं को कितना रोजगार दे रहे हैं यह मायने रखता है? यदि इन उद्योगों से प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिल रहा होता तो प्रदेश का युवा आज सड़कों पर ना होता

पर्यटन विभाग को 302 करोड़ अलॉट किया गया है सबसे पहला प्रश्न तो यह उठता है कि जितना पैसा का प्रावधान किया गया है उतना धरातल पर खर्च भी होगा क्या?मूलभूत संरचना के लिए ₹60 करोड़ का प्रावधान रखा गया है ये किस आधार पर हुआ?क्या कोई सर्वे हुआ जिसके आधार पर ₹60 करोड़ अलॉट कर दिया गया। प्रदेश भर की सड़क के गड्ढे क्या 60 करोड़ में भर जाएंगे?

शिक्षा को 10459 करोड़ दी गई है परंतु सबसे बड़ा सवाल यह उठता है शिक्षा विभाग को प्रदेश की आमदनी का सबसे बड़ा हिस्सा दिए जाने के बावजूद दुखद पहलू यह है कि प्रदेश में लगातार पलायन हो रहा है।

अच्छी यूनिवर्सिटी अच्छे इंस्टिट्यूट के अभाव में पर्वतीय अंचलों से लोग देहरादून आ रहे हैं और देहरादून से भी दिल्ली या मुंबई के लिए पलायन कर जा रहे हैं।

बड़ा सवाल यह है कि क्या राज्य सरकार जो यह लोक लुभावनी योजनाएं ला रही है जैसे वर्क फोर्स डेवलपमेंट,मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना इनका कोई फॉलोअप भी होगा क्या अधिकारी इन योजनाओं को परसू करेंगे ?क्या योजनाएं जितनी खूबसूरत दिखाई पड़ रही हैं धरातल उतरेंगी भी?

मोटा अनाज यानी राष्ट्रव्यापी मिलेट योजना को मात्र 20 करोड़ देना हर लिहाज से नाकाफी है। कोदा झिंगुरा जेसे अनाजों को अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाने में कांग्रेस का बहुत बड़ा योगदान है।

मोटे अनाज के लिए जैविक खाद की जरूरत पड़ती है और उत्पादन अच्छा खासा हो जाता है इसमें कमर्शियल फर्टिलाइजर यूरिया वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती ऐसे में राज्य सरकार को चाहिए था कि मोटे अनाज की दिशा में बजटीय प्रावधान और ज्यादा का होना चाहिए था ताकि स्थानीय फसलों को प्रोत्साहन मिले और गांव गांव गांव में इसका प्रचार-प्रसार हो।

बजट के लिहाज से यदि देखा जाए तो बजटीय प्रावधान तो अच्छा खासा है परंतु स्वास्थ्य विभाग का बदसूरत सच यह है कि स्वास्थ्य विभाग की महत्वाकांक्षी योजनाएं जेसे नेशनल हेल्थ मिशन एनएचएम हर वर्ष बजट का 60% भी खर्च नहीं कर पाते वर्ष 2022-23 में भी यही देखने को मिला जोकि अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है।

पिछले बजट में नंदा गौरा योजना के लिए सरकार ने 500 करोड़ का प्रावधान रखा था, जोकि इस बार घटाकर 282 करोड़ कर दिया है।

कुल मिलाकर राज्य सरकार को अपनी आमदनी की कैपेसिटी को बढ़ाना होगा यदि ऐसा नहीं हुआ तो राज्य पर कर्ज बढ़ेगा और उत्तराखंड कमजोर होगा।

कुल मिलाकर इस बजट से इतना ही पता चलता है कि राज्य सरकार ने राजस्व वृद्धि की दिशा में कोई कारगर कदम नहीं उठाया है। उत्तराखंड राज्य खनन और आबकारी से हो रही आमदनी पर ही निर्भर है।

चार धाम यात्रा जो कि उत्तराखंड की यूएसपी है उसमे सुविधाएं बढ़ाने के लिए मात्र 10 करोड़ के प्रावधान का क्या औचित्य है?

कुल मिलाकर यह बजट आंकड़ों के मकड़जाल के अलावा और कुछ नहीं है। केंद्र पोषित योजनाओं के सहारे राज्य चल रहा है यदि उनको हटा दिया जाए तो राज्य के पास अपनी कोई कारगर योजना नहीं है जिससे उत्तराखंड का विकास हो सके।

जल जीवन मिशन दीनदयाल उपाध्याय आवास योजना प्रधानमंत्री आवास योजना पीएमजीएसवाई इत्यादि के सहारे राज्य को बैलगाड़ी पर विकास के रास्ते पर चलने की कोशिश की जा रही है।

कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि ना ही इस बजट में महिलाओं के लिए ना ही युवाओं के लिए न ही प्रदेश के किसान मजदूर और व्यापारियों के लिए कुछ भी हितकर है।

राकेश राणा (अध्यक्ष)
जिला कांग्रेस कमेटी टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड

गया स्नातक व शिक्षक बिधान परिषद क्षेत्र चुनाव को लेकर महागठबंधन की बैठक सम्पन्न

पटना । कांग्रेस दर्पण

गया स्नातक व शिक्षक चुनाव को लेकर सोमवार को अरवल शहर के अशोका होटल में महागठबंधन की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता राजद जिलाध्यक्ष जगजीवन राम ने किया, बैठक में कांग्रेस जिलाध्यक्ष डॉ धनंजय शर्मा, कोषाध्यक्ष एडवोकेट निसार अख्तर अंसारी, उपाध्यक्ष श्री कामेश्वर शर्मा, प्रो मदन यादव, बंशी प्रखंड अध्यक्ष मो कैफ, कलेर प्रखंड अध्यक्ष काशीराम पासवान, महासचिव नईमुद्दीन अंसारी,सुरेंद्र यादव, इमरान खान, पप्पू कुमार के अलावे भाकपा माले के जितेंद्र यादव, रविंदर यादव राजद के घनश्याम वर्मा, जगजीवन राम, जदयू के जिलाध्यक्ष रामकिशोर बर्मा सहीत बड़ी संख्या में महागठबंधन के नेता एवं कार्यकर्ता शामिल हुए । बैठक में गया स्नातक क्षेत्र के महागठबंधन समर्थित राजद उम्मीदवार प्रो पुणीत कुमार सिंह भी शिरकत किए,

सभी लोग एक स्वर में महागठबंधन के स्नातक प्रत्याशी डॉ पुनीत सिंह एवं शिक्षक प्रत्याशी संजीव श्याम सिंह को ऐतिहासिक जीत दिलाने की बात कही. वहीं स्नातक प्रत्याशी डॉ पुनीत सिंह ने क्षेत्र के विकास के लिए प्रतिबद्धता दिखाई। उन्होंने आगे कहा कि जीत के बाद महागठबंधन के सभी कार्यकर्ताओं का मान सम्मान का ख्याल रखते हुए क्षेत्र का विकास मैं तेजी से करूंगा।

लोगों ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एवं उपमुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव के विकास कार्यों के आधार पर महागठबंधन के प्रत्याशी की एक बड़ी जीत होगी। कांग्रेस जिलाध्यक्ष डॉ धनंजय शर्मा ने महागठबंधन के कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर आगामी 31 मार्च को एक एक मत महागठबंधन के प्रत्याशियों पक्ष में देने एवं दिलाने की अपील किया।

काँग्रेस जिला कोषाध्यक्ष एडवोकेट निसार अख्तर अंसारी ने राजद द्वारा गठबन्धन के साथी दलों के साथ और बेहतर तालमेल करने पर बल दिया गया,

बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी पिछड़ा एवं अति पिछड़ा विभाग के अध्यक्ष अनुराग चंदनने राहुल गांधी के ऊपर 5 दिनों में तीसरी बार पुलिस के राहुल गांधी के आवास पर जाने को लेकर कांग्रेस ने नाराजगी जताई है उन्होंने इसकी निंदा करते हुए केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए इसे उत्पीड़न और राजनीतिक प्रतिशोध का सबसे खराब मामला बताया उन्होंने कहा भाजपा अब बहुत हो चुका अगर आप अपने करतूत से बाज बाज नहीं आएंगे तो आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा इसके लिए पूरे बिहार में एक जन आंदोलन छेड़ा जाएगा

जय कांग्रेस राहुल गांधी जिंदाबाद

उत्तराखंड में घाटे के बजट को पूरा करने को महंगाई डायन की मार, आमजन लाचार: लालचंद शर्मा

पटना। कांग्रेस दर्पण

उत्तराखंड में राज्य सरकार के घाटे के बजट को पूरा करने के लिए अब आमजन पर महंगाई की मार का चाबुक पड़ने लगा है। देहरादून महानगर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष लालचंद शर्मा ने प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लेकर आमजन को महंगाई के बोझ तले दबाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार की आर्थिक नीति पूरी तरह से फ्लॉप है। घाटे का बजट सरकार ने पेश किया। अब घाटा पूरा करने के लिए लोगों पर महंगाई का चाबुक चलाया जा रहा है। चाहे घर बनाने के लिए जमीन खरीदना हो, या फिर देहरादून से दिल्ली सफर करना हो। सभी में रेट बढ़ा दिए गए हैं। वहीं, अब बिजली और पानी के रेट बढ़ाने की भी तैयारी है। ऐसे में जनता पर चौतरफा महंगाई का हमला होने जा रहा है। कांग्रेस हाथ पर हाथ धरे चुप नहीं रहेगी और जनता के साथ सड़क पर उतरेगी।

घाटे का बजट

लालचंद शर्मा ने एक बयान में कहा कि हाल ही में 17 मार्च को उत्तराखंड सरकार ने ग्रीष्मकालीन विधानसभा गैरसैंण में वर्ष 2023-24 का बजट पेश किया गया और इसे पारित किया गया। सरकार ने पिछले साल की तुलना में 18 फीसद की वृद्धि के साथ 77407 करोड़ का बजट पेश किया। इसके लिए 24744.31 करोड़ रुपए सरकार अपने संसाधनों से जुटाएगी। फिर सवाल उठता है कि बाकी 52663 करोड रुपए सरकार कहां से जुटाएगी। इसका उल्लेख बजट में स्पष्ट रूप से नहीं किया गया है। या तो सरकार अपने बाकी कामों को पूरा करने के लिए बाजार से कर्ज ले कर के फिर उत्तराखंड को कर्ज में डूबाने का काम करेगी। अब तो साफ है कि बिजली, पानी सहित अन्य मदों से राजस्व बढ़ाकर कुछ घाटे को पाटने का काम किया जा रहा है।

पानी की आपूर्ति लचर, कई जगह गंदा पानी, अब बढ़ेंगे रेट

लालचंद शर्मा ने कहा कि पानी की आपूर्ति राजधानी देहरादून में ही लचर है। कई स्थानों पर गंदे पानी की आपूर्ति हो रही है। वहीं, कई स्थानों पर एक बूंद पानी तक नहीं आ रहा है। अब प्रदेश सरकार एक अप्रैल से उत्तराखंड में पीने का पानी भी नौ से 15 फीसदी तक महंगा करने जा रही है। इसका कड़ा विरोध किया जाएगा।

बिजली की भी पड़ने वाली है मार

लालचंद शर्मा ने कहा कि उत्तराखंड में एक अप्रैल से बिजली दरों में 12 फीसदी तक बढ़ोतरी करने की सूचना मिल रही है। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने इस पर मुहर लगा दी है। आयोग 23 मार्च को बढ़ी हुई दरें जारी कर देगा। ऐसे में उपभोक्ताओं पर महंगाई की मार दोहरी पड़ने वाली है। उन्होंने कहा कि पिछले साल 2022 में बिजली की दरों में तीन बार वृद्धि की गई थी। पिछले साल उत्तराखंड में एक साल में 26 पैसे से लेकर 1.11 रुपये प्रति यूनिट तक बिजली के दर में तीन बार बढ़ोत्तरी की गई थी। एक अप्रैल से बिजली की दरों में 2.68 फीसद की वृद्धि हुई। सितंबर में 3.85 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी के बाद अक्टूबर में सात पैसे प्रति यूनिट बढ़ाए गए। अब फिर से रेट बढ़ने से लोगों की परेशानी बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि राजधानी देहरादून में बिजली की लचर आपूर्ति किसी से छिपी नहीं है। बार बार बिजली जाने से लोग परेशान हैं।

मकान बनाना भी हुआ मुश्किल

उन्होंने कहा कि राज्य में जमीन के सर्किल रेट में 33.6 प्रतिशत की बढ़ोतरी पहले ही की जा चुकी है। सर्किल रेट में औसत बढ़ोतरी 33.6 प्रतिशत है। कृषि की जमीनों की दरों में 32.47 और अकृषि जमीनों की दरों औसत 34.83 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में अब कोई आम व्यक्ति अपना मकान बनाने के लिए दस बार सोचेगा। कौन का ऐसा क्षेत्र है जहां सरकार जनता को निचौड़ नहीं रही है।

बसों का पहले ही बढ़ा दिया गया किराया

उन्होंने कहा कि पिछले महीने उत्तराखंड की यूपी से होकर गुजरने वाली बसों का किराया बढ़ा दिया गया था। परिवहन निगम ने 13 ऐसे रूटों पर किराये में पांच रुपये से लेकर 60 रुपये तक की बढ़ोतरी लागू की है। ऐसे में देहरादून से दिल्ली का सफर भी महंगा हो चुका है। उन्होंने कहा कि चौतरफा महंगाई से जनता त्रस्त हो चुकी है। वहीं, केंद्र की ओर से भी महंगाई का डबल इंजन का चाबुक चल रहा है। रसोई गैस का घरेलू सिलेंडर अब देहरादून में 1122 रुपये का हो चुका है। ऐसे में अब रसोई का बजट भी पूरी तरह से बिगड़ चुका है। वहीं, वर्ष 2014 से पहले सिलेंडर की कीमत 410 रुपये थी। वहीं तब पेट्रोल की कीमत 36.81 रुपये थी, जो अब सौ रुपये के करीब है। आठ साल में केंद्र और राज्य सरकारों ने जनता को बेहाल कर दिया है।

बच्चों की स्टेशनरी के बजट पर भी जीएसटी की मार

लालचंद शर्मा ने कहा कि कागज और स्याही पर जीएसटी बढ़ने से बच्चों की शिक्षा का बजट भी बिगड़ चुका है। स्टेशनरी के रेट 20 फीसद तक बढ़ गए हैं। मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, नवीं कक्षा का बैग अब आठ हजार रुपये में तैयार हो रहा है, जबकि वर्ष 2014 में डेढ़ से दो हजार रुपये इसकी कीमत थी।

लाल चंद शर्मा
पूर्व महानगर अध्यक्ष
देहरादून कांग्रेस

उत्तर प्रदेश सरकार को सौंपा ज्ञापन

पटना। कांग्रेस दर्पण

भारतीय किसान यूनियन प्रधान के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश प्रधान जी एवम सभी पद अधिकारीयों के द्वारा जिला अधिकारी बिजनौर के द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार को ज्ञापन दिया गया..

जिसमें लिंक रोड की मरम्मत, गांव में जर्जर बिजली के तारों को बदलने, आवारा पशुओं की व्यवस्था, 300यूनिट बिजली गांव के प्रत्येक घर में मुफ्त, 60वर्ष से अधिक आयु के किसानों को प्रत्येक महा पांच हजार रुपए पेंशन, आन्दोलन के दौरान किसानों पर दर्ज मुकदमें वापस लिए जाए, समय से नहरों में पानी छोड़ा जाए, आदि मुद्दों पर तुरन्त कार्यवाही की जाए,

अधिवक्ता रीता भुइयार नजीबाबाद जिला बिजनौर

आवश्यक सूचना

दिनांक 21 मार्च 2023 को प्रदेश कांग्रेस कमेटी के माननीय अध्यक्ष श्री करन माहरा जी, हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम के राज्य प्रभारी श्री अजय कुमार लल्लू जी, हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के लोकसभा प्रभारी पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी, संयोजक, पूर्व मंत्री श्री नवप्रभात जी एवं राष्ट्रीय सचिव काजी निजामुद्दीन के संयुक्त नेतृत्व में ₹हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम₹ के तहत पदयात्रा निकाली जाएगी।
दिनांक 21 मार्च 2023, सांय 04:00 बजे से
स्थान :- सैनी धर्मशाला, आजाद नगर चौक पर एकत्र होकर तदुपरांत सुभाष नगर से पनियाला तक, रुड़की, जिला-हरिद्वार
अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त कार्यक्रम को सफल बनाए जाने हेतु पदाधिकारियों/साथियों सहित प्रतिभाग करने का कष्ट करेंगे।

आशीष सैनी
प्रदेश अध्यक्ष/चैयरमेन, ओबीसी विभाग
उत्तराखण्ड प्रदेश कांग्रेस कमेटी

हमिद नगर बराज से निकलने वाली नहर विगत 54 वर्षो लंबित पड़ी है किसानों के खेत में 54 वर्ष बीत जाने के बाद भी किसानों को खेतों तक पानी नहीं पहुंची सरकार की लचर व्यवस्था के खिलाफ आज 20-03-2023को तीसरा दिन पैदल मार्च में शिरकत करते हुए जहानाबाद के शहर से पटना राजभवन की ओर कुच करते कांग्रेस नेता राम विनय सिंह यादव, श्याम सुंदर यादव, मनोज सिंह यादव, रविंद्र कुमार उर्फ बजरंगी जी, एवं बहुत सारे संघर्ष के साथी, किसान बंधुओं

दिनांक 20 मार्च 2023 को साधन सहकारी समिति के संपन्न हुए चुनाव में कांटे के टक्कर में अध्यक्ष पद का चुनाव जीतने वाले काशी विद्यापीठ ब्लॉक के केसरीपुर से कांग्रेस पार्टी से निर्विरोध जिला सचिव श्री गोपाल पटेल जी, सेवापुरी ब्लॉक से श्री संजय सिंह जी एवं पिंडरा ब्लॉक कर्मी, बैकुंठपुर से श्री गिरीश गौरव जी को जिला कांग्रेस कमेटी के कैंप कार्यालय चांदपुर में अंगवत्रम देकर, मल्यार्पण कर सम्मानित करते हुए।

मोदी अडानी भाई -भाई,
देश बेचकर खाई मलाई...

#अडानीमहाघोटाला पर केंद्र सरकार की चुप्पी के खिलाफ मधेपुरा एनएसयूआई इकाई ने जिलाध्यक्ष निशांत यादव के नेतृत्व में शहर में विरोध मार्च निकला गया ।

हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम बेगूसराय जिला कांग्रेस के बरौनी प्रखंड ओमप्रकाश सिंह,बीहट नगर अध्यक्ष पवन कुमार एवं छौड़ाही प्रखंड अध्यक्ष राजेश महतों के नेतृत्व में सफल कार्यक्रम

दिल्ली पुलिसः
निरंकुश सत्ता का नया टूल

पटना ।कांग्रेस दर्पण

बलात्कारियों और लुटेरों को पकड़ने में अक्सर नाकाम रहने वाली दिल्ली पुलिस इन दिनों विपक्ष के खिलाफ आवश्यकता से अधिक सक्रिय है। राहुल गांधी की आवाज दबाने के लिए मोदी सरकार दिल्ली पुलिस का अनर्गल इस्तेमाल कर रही है और पुलिस भी बगैर किसी प्रतिरोध के तानाशाही मानसिकता के आगे नतमस्तक हो चुकी है।

नोटिस के बहाने कांग्रेस को परेशान करने वाली दिल्ली पुलिस राहुल गांधी से उन महिलाओं की जानकारी मांग रही है, जिनके यौन शोषण होने की बात राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा के समय की थी। जबकि राहुल गांधी ने यह भी कहा था कि ‘‘जब मैं उनसे बोलता था कि मैं पुलिस से कहूं, तो वे कहती थीं कि पुलिस को मत बताइए। हम चाहते थे कि हम आपको बताएं, लेकिन आप पुलिस को मत बताइए। इससे हमारी मुसीबतें और बढ़ जाएंगी।₹

ये सब बातें दिल्ली पुलिस को कहां समझ आने वाली हैं?

यह बात जितनी चिंताजनक है.. उससे अधिक प्रोपेगेंडा से भरपूर कि दिल्ली पुलिस को कार्रवाई करने की बात 45 दिन बाद क्यों याद आई... क्या इतने दिन पुलिस सो रही थी?

दिल्ली में रोजाना छः महिलाओं के साथ बलात्कार और साथ के साथ छेड़छाड़ होती है। ये अपराध हर साल घटने की बजाए बढ़ रहे हैं। बीते साल में महिला अपराध के मामलों में 41 फीसदी की बढोत्तरी के साथ दिल्ली महिलाओं के लिए देश की सबसे खतरनाक मेट्रो सिटी बन चुकी है।

मगर, अपराध रोकने में लगभग नाकाम दिल्ली पुलिस और सरकार को यह सब नहीं दिखाई देता।

दरअसल, दिल्ली पुलिस राहुल गांधी की उस छवि को नुकसान पहुंचाना चाहती है, जिसके लिए भाजपा और उसकी अधकचरी आईटीसेल ने अरबों रूपये बर्बाद कर दिए। मगर राहुल गांधी और कांग्रेस का बाल भी बांका न कर सकी।

ये देखकर हंसी भी आती है और दुख भी होता है कि ....लोकतंत्र और संविधान का गला घोंटने वाली निरंकुश मोदी सरकार के वो नेता भी महिलाओं को सुरक्षा देने की बात कर रहे हैं, जो चिन्मयानंद और कुलदीप सेंगर के लिए दिनदहाड़े नारे लगाते नजर आते हैं।

अब उनको भी महिलाओं की चिंता सताने लगी है, जिन्हें बिलकिस बानो के रेपिस्ट संस्कारी और हाथरस मामले के आरोपी रिश्तेदार लगते हैं।

यह राहुल गांधी की शख्सियत का करिश्मा ही है कि उन लोगों को भी महिलाओं की चिंता सताने लगी है, जिन्हें अंकिता भंडारी के कातिल .... जिन्हें कठुआ के दुष्कर्मी... जिन्हें आसाराम और रामरहीम आज भी मासूम और समाजसेवी लगते हैं।

यह बात पूरा देश जानता है कि कांग्रेस की पूर्व सरकारों ने महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए जो कुछ भी किया है, वह अन्य सरकारों के लिए एक नजीर है।

आगे भी कांग्रेस और राहुल गांधी महिलाओं के मुद्दे पर निरंतर आवाज़ उठाते रहेंगे।

खेती एक जुआ है ,आज की घण्टों हुई तबाही की बारिश ने यह सिद्ध कर दिया।

दुख की बात है कि किसान पहले खाद की क़ल्लित से परेशान रहे, फिर घंटों लाइन में लगकर व अधिक दामों पर खाद ख़रीद कर खेतों में दिया। अब बेमौसम बरसात ने पूरा का पूरा फसल बर्बाद कर दिया।

ऐसे में सरकार से मेरी यही माँग है कि रबी फसलों की बर्बादी के लिये किसानों को शीघ्र मुआवज़ा देने की घोषणा करे.

.... रणजीत कुमार मुखिया जी, पूर्व सचिव बेगूसराय काँग्रेस कमिटी।

दो दिवसीय प्रशिक्षण शिविर
दिनांक : 21-22 मार्च, 2023
स्थान : जगजीवन राम शोध संस्थान, पटना
युवा क्रांति
भारतीय युवा कांग्रेस
बुनियादी
प्रशिक्षण शिविर
बिहार प्रदेश युवा कांग्रेस
/BiharPradeshYouthCongressOfficial
@IYCBihar
/bihar_youth_congress